देश की 60 फीसदी भूमि पर भूकंप का खतरा

कानपुर: भारत में कई बार भूकंप ने कहर बरपाया है, लेकिन विदेशों के मुकाबले न तो सरकार ही इसके प्रति जागरूक है न ही लोग। आज भी लोग इमारतें बनाने में भूकंपरोधी होने का ध्यान नहीं देते। यह कहना है आईआईटी में भूकंपरोधी इमारतों पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने आये भारत के जाने-माने आर्किटेक्चरल और सिविल इंजीनियरों का। उन्होंने बताया कि देश का 60 फीसदी भूभाग भूकंप के जोन में है, फिर भी सरकार की ओर से इमारतों के भूकंपरोधी होने पर कोई नियम नहीं बना है। हालांकि गुजरात जैसे राज्य जहां इसका खतरा सबसे ज्यादा है, वहां इस पर बेहतर काम हो रहा है।

बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर केया मित्रा का कहना है कि बढ़ते शहरीकरण से भूकंप का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि निर्माणों के दौरान जमीनों की जांच सही तरीके से नहीं होती। ऐसी जमीनों पर भी निर्माण हो जाता है, जहां नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नक्शे पास करने के दौरान भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि अमेरिका आदि देश में इसे जरूरी कर दिया गया है। पुणे आर्किटेक्चर कॉलेज फॉर वीमेन मीरा शिरोडकर का कहना है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन आदि देशों में आपदा प्रबंधन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। वहां नक्शा पास करने वाले इंजीनियरों को बहुत कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ता है। सूरत से आयीं आर्किटेक्ट डॉ भावना का कहना है भारत में सबसे ज्यादा खतरा उत्तर पश्चिम क्षेत्र जम्मू-कश्मीर उत्तराखंड आदि में है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कम खतरा नहीं है, लेकिन यहां आपदाओं से निपटने से सक्षम निर्माण लगभग शून्य है। हालांकि खतरों को भांपते हुए गुजरात इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है। इन इंजीनियरों का कहना है कि भूकंप के खतरों को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि लोगों में जागरूकता आये। सरकार निर्माण के नियमों, लैंड रगुलेशन को सुधारे और इमारतों को भूकंप के खतरों से निपटने के उपाय को जरूरी बनाये।